

भारत का राजपत्र

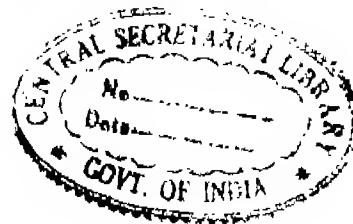
The Gazette of India



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 327]
No. 327]

नई दिल्ली, बुधवार, 9, 1996/आश्विन 17, 1918
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 1996/ASVINA 17, 1918

विदेश मंत्रालय
(विधि और सम्बिधान प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 1996

सा.का.नि. 462 (अ)।—युनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड तथा स्विस परिसंघीय परिषद के बीच तारीख 26 नवम्बर, 1880 को बर्न में सम्पन्न और हस्ताक्षरित प्रत्यार्पण सम्मिलित तारीख 29 जून, 1904 के अधिसमय द्वारा यथासंशोधित, भारत और स्विटजरलैंड के बीच प्रवृत्त मानी जाती है;

और केन्द्रीय सरकार ने, प्रत्यार्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश सं. सा.का.नि. 56 तारीख 5 जनवरी, 1963 द्वारा निदेश दिया था कि अध्याय 3 से भिन्न उक्त अधिनियम के उपबंध स्विटजरलैंड को लागू होंगे :

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पूर्वोक्त सम्बिधान को निम्नलिखित रूप से उपर्युक्त करती है :—

अनुच्छेद 1

युनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महामहिम सामाजी वर्तमान संविधान में अनुबन्ध परिस्थितियों के अधीन और शारीर पर उन सभी व्यक्तियों को, तथा स्विस परिसंघीय परिषद् द्वारा प्रकार की परिस्थितियों के अधीन और शारीर पर, स्विस नागरिकों के सिवाए, उन सभी व्यक्तियों को एक-दूसरे को सौंप देंगी, जिनमें दोनों उच्च संविदाकारी पक्षकारों में से किसी एक के अधिकरणों द्वारा अनुच्छेद 2 में प्रगतिशील ऐसे अपराधों और दोषों के लिए जो किसी एक पक्ष के राज्य क्षेत्र में किए गए हों, आरोपित

अधिकार सिद्धदोष पाया गया हो, तथा जो दूसरे पक्ष के राज्य क्षेत्र में पाए गए हों।

यदि परिसंघीय परिषद् ऐसे व्यक्तियों को, उसकी स्विस राष्ट्रियता के कारण ग्रापर्वित करने में असमर्थ हो, जिसने अनुच्छेद 2 में वर्णित कोई अपराध युनाइटेड किंगडम में करने के पश्चात् स्विटजरलैंड में शरण ले ली हो, तो उस स्थिति में परिसंघीय परिषद् उस व्यक्तियों के खिलाफ लागे आरोप को उसके मूल प्रवास स्थान की संधि के अनुसार विधिक प्रभाव देने और उस पर मुकदमा चलाने के लिए वचनबद्ध हैं तथा युनाइटेड किंगडम की सरकार उस मामले से सम्बद्ध सभी दस्तावेज, अधिसाक्षय और सबूत देने और आनुग्रहिक निष्पादन हेतु स्विस न्यायाधीश द्वारा निर्देशित तथा उन्हित राजनयिक माध्यम से सम्प्रेषित जांच करवाने के लिए वचनबद्ध है।

अनुच्छेद 2

जिन अपराधों के लिए प्रत्यर्पण किया जाना है वे निम्न प्रकार हैं :—

1. हत्या (जिनमें शिशुहत्या भी शामिल है) और हत्या करने का प्रयत्न।
2. भानव हत्या।
3. मुद्रा का बूटकरण या परिषर्तन, कूटकृत या परिवर्तित मुद्रा को छलाना या प्रचलन में लाना।
4. कूटरचना, या कूटकरण या कूटकृत या दस्तावेजों को छलाना, या परिवर्तित करना, दोनों राज्यों की दण्ड संहिताओं में उल्लिखित अपराधों यथा कागजी मुद्रा बैंक प्रलेखों, या अन्य प्रतिभूतियों का कूटरचना तथा मिथ्याकरण, या अन्य सार्वजनिक या निजी दस्तावेजों में कूटकरण, या उनका मिथ्याकरण को शामिल करना। इसी प्रकार ऐसे कूटकृत, कूटरचित या मिथ्याकृत कागजात को छलाना या प्रचलन में लाना या स्वेच्छा से ऐसे कूटकृत, कूटरचित या मिथ्याकृत कागजातों का उपयोग करना।

5. गवन या चोरी।
6. मिथ्या आधार पर धन या माल प्राप्त करना।
7. दिवालिया विधि के विरुद्ध अपराध।
8. किसी दूषनिहिती, अंकर, अधिकारी, फैक्टर, न्यासी या किसी कंपनी के निदेशक या संदस्य या लोक अधिकारी द्वारा किए गए कपट, तस्मय ब्रूक्ष किसी विधि द्वारा अपराध ठहराया गया हो।
9. बलासंग।
10. अव्यस्कों द्वारा अपहरण।
11. बच्चों को चुराना या उनका व्यपहरण।
12. चोरी या अपराधिक आशय से गृह भेदन।
13. आगजनी।
14. हिन्सक लूट।
15. उद्धापन के आशय से पत्र द्वारा अथवा अन्यथा धमकियां देना।
16. शपथ भंग या शपथ भंग का कार्य करना।
17. सम्पत्ति की विदेशपूर्ण क्षति यदि उक्ता अपराध अभ्यारोज्य हो,

प्रत्यर्पण तथ्य से पूर्व या पश्चात् उपकार्याता के रूप में पूर्वोक्त किसी अपराध में सहभागिता के लिए भी किया जाएगा परन्तु ऐसी सहभागिता दोनों संविदाकारी पक्षकारों की विधियों द्वारा दंडनीय होगी।

अनुच्छेद 3

किसी भागीड़े अपराधी को किसी पुलिस मजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ दी पीस या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी जानकारी या शिकायत और ऐसे साक्ष्य पर जारी किए गए वारंट के अधीन या ऐसी कार्यवाहियों के पश्चात् जीवारंट जारी करने वाले प्राधिकारी की राय में वारंट के जारी किए जाने को न्यायोचित ठहराता है, किसी भी देश में पकड़ा जा सकेगा, यदि अपराध दोनों संविदाकारी पक्षकारों के अधिक्षेत्र के ऐसे भागों में किया गया था या उस व्यक्ति को दोषसिद्ध किया गया था जिसमें मजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ दी पीस या अन्य सक्षम प्राधिकारी अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है परन्तु यह कि युनाइटेड किंगडम में ऐसे मामले में अभियुक्त को लंदन में पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष अथवासंभव शीश्रता से भेजा जाएगा।

अनन्तिम गिरफ्तारी के लिए अध्यपेक्षा छाक या तार द्वारा भेजी जा सकेगी परन्तु उन्हें किसी न्यायिक या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा भेजा गया तात्पर्यित होना चाहिए। ऐसी अध्यपेक्षाओं में अपराध का सामान्य शब्दों में वर्णन और यह एक कथन होना चाहिए कि अपराधी को गिरफ्तारी के लिए वारंट मंजूर किया गया है और यह कि उसका प्रत्यर्पण चाहित होगा।

यदि इस संधि के अनुबंधों के अनुसार उसके अभ्यर्पण का दावा करने वाले राजनीतिक अभिकर्ता द्वारा तीस दिन की अवधि के भीतर प्रत्यर्पण के लिए अध्यपेक्षा नहीं की जाएगी तो उसे इस अनुच्छेद के अनुसार युनाइटेड किंगडम और स्विटजरलैंड में भी उन्मोक्षित कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद 4

प्रत्यर्पण के लिए अध्यपेक्षा संघर राजनीतिक भाष्यम से और स्विटजरलैंड में ब्रिटेन के मंत्री द्वारा परिसंघ के अध्यक्ष और युनाइटेड किंगडम में लंदन में स्विस महाकौसल द्वारा विदेशी जारी के सेक्रेट्री ऑफ स्टेट की जाएगी, जो, इस संधि को प्रयोजनों के लिए महामहिम द्वारा स्विटजरलैंड राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में इसके द्वारा मान्यताप्राप्त है।

अनुच्छेद 5

स्विटजरलैंड में कार्यवाहियों की रीति निम्नलिखित होगी :—

किसी अभियुक्त व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए अध्यपेक्षा सक्षम अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी गिरफ्तारी के वारंट की एक अधिप्रमाणित प्रति के साथ की जाएगी जिसमें ऐसे अपराध को स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाएगा जिसके लिए वह अभियुक्त है, इसके साथ ऐसे तथ्य और सूक्ष्य, जिनके आधार पर वारंट मंजूर किया गया है, का उल्लेख करते हुए उचित रूप से दी गई वैध जानकारी भी होनी चाहिए।

यदि अध्यपेक्षा ऐसे व्यक्ति के संबंध में है जिसको पहले ही सिद्धदोष ठहराया जा चुका है तो इसके साथ ऐसे अपराध जिसके लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था, का उल्लेख करने वाले दंडादेश या दोष की अधिप्रमाणित प्रति भी होनी चाहिए।

अध्यापेक्षा के साथ दावाकृत व्यक्ति का विवरण भी होना चाहिए और यदि यह संभव हो तो ऐसी अन्य जानकारी और विशिष्टियां भी होनी चाहिए जो उसकी पहचान कराएंगी।

इन दस्तावेजों की जांच करने के पश्चात् स्विस परिसंघीय परिषद् उन्हें प्रादेशिक सरकार को, जिसके राष्ट्रक्षेत्र में आरोपित व्यक्ति पाया जाता है, संप्रेषित करेगी ताकि उनकी विषयवस्तु के आधार पर न्यायिक या पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी जांच की जा सके।

प्रादेशिक सरकार जांच के मौखिक परिणाम उसके साथ सभी दस्तावेजों को, यदि कोई हो, अधिक व्यौरेवार रिपोर्ट के द्वारा परिसंघीय परिषद् को संप्रेषित करेगी जो उम्मीदी जांच करने के पश्चात् और किसी भी पक्ष द्वारा विरोध न किए जाने पर, प्रत्यर्पण मंजूर करेगी और अपना निर्णय ब्रिटेन के दूतावास और प्रश्नगार प्रादेशिक सरकार को भेजेगी। पश्चात्कर्ता को इसलिए कि वह अभ्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति को सीमावर्ती क्षेत्र में ऐसे स्थानों पर भेज सके और उसे ऐसे पुलिस प्राधिकारी के सुपुर्द कर सके जिन्हें ब्रिटेन का दूतावास प्रत्येक विशेष मामले में नामनिर्दिष्ट करे।

यदि तथ्यों को साक्षित या अभियुक्त की पहचान स्थापित करने की दृष्टि से प्रस्तुत किए गए दस्तावेज या स्विस प्राधिकारियों द्वारा एकत्रित किए गए विवरण अपर्याप्त होते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन के राजनीतिक प्रतिनिधि को तुरंत सूचना दी जाएगी ताकि वह और साक्ष्य प्रस्तुत कर सके। यदि ऐसे और साक्ष्य पन्द्रह दिन के भीतर प्रस्तुत नहीं किए जाते तो गिरफ्तार व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाएगा।

इस संधि के लागू होने का प्रतिवाद किए जाने की दशा में स्विस परिसंघीय परिषद् दस्तावेजों ("दोजियर्स") को स्विस परिसंघीय अधिकारण को, संप्रेषित करेगी, जिसका कर्तव्य इस प्रश्न को निश्चित रूप से विनिश्चित करना है कि प्रत्यर्पण मंजूर किया जाना चाहिए या नहीं।

परिसंघीय परिषद् परिसंघीय अधिकारण के निर्णय को ब्रिटेन के दूतावास को भेजेगी। यदि वह निर्णय प्रत्यर्पण मंजूर करता है तो परिसंघीय परिषद् इसके निष्पादन का आदेश देगा, जैसा कि उस मामले में होता है जब परिसंघीय परिषद् स्वयं प्रत्यर्पण मंजूर करती है। यदि दूसरी तरफ परिसंघीय अधिकारण प्रत्यर्पण भासंजूर कर देती है तो परिसंघीय परिषद् तुरंत अभियुक्त को मुक्त करने का आदेश देगी।

अनुच्छेद 6

ब्रिटेन की महामहिम साम्राज्यी के अधिक्षेत्र में, महामहिम साम्राज्यी के उपनिवेशों या कब्जाधीन विदेशी क्षेत्रों से भिन्न, कार्यवाही की रीति निम्नलिखित होगी :—

(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति की दशा में अभ्यर्पण की अध्यपेक्षा स्विस परिसंघ के राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा ब्रिटेन की महामहिम सप्राज्ञी के विदेशी कार्यों के प्रमुख सेक्रेट्री ऑफ स्टेट को की जाएगी। उक्त मांग के साथ, स्विटजरलैंड में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित कार्यों का संज्ञान करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी का वारंट या अन्य समतुल्य न्यायिक दस्तावेज और किसी ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के समक्ष सम्यक रूप से किए गए अभिसाक्ष्य या कथन जो शपथपूर्वक सत्यानिष्ठा से सत्य घोषित किए गए हैं और जिनमें दावाकृत व्यक्ति के विवरण और कोई विशिष्टियां, जो उसकी पहचान साबित कर सके अन्तर्भूत होंगी।

राज्य का उक्त प्रमुख सचिव ऐसे दस्तावेजों को ब्रिटेन की महामहिम सप्राज्ञी के गृह विभाग के राज्य के प्रमुख सचिव को संप्रेषित करेगा जो तब अपने हस्ताक्षर और मोहर के अधीन आदेश द्वारा लंदन में किसी पुलिस मजिस्ट्रेट को यह संज्ञापित करेगा कि उससे ऐसी अध्यपेक्षा की गई है और यदि कोई सम्यक कारण हों तो कि प्रपलायियों के पकड़े जाने के लिए उसका वारंट जारी करेगा।

सेक्रेट्री ऑफ स्टेट के ऐसे आदेश की प्राप्ति पर और ऐसे साक्षों के प्रस्तुत किए जाने पर जो मजिस्ट्रेट की राय में वारंट के जारी किए जाने को न्यायोचित ठहराते हैं, यदि अपराध युनाइटेड किंगडम में किया गया था तो वह तदमुसार उसका वारंट जारी करेगा।

जब दावाकृत व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसे वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष, या लंदन में किसी अन्य पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा। यदि तत्समय प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य ऐसे हैं जो बंदी विचारण के लिए सुपुर्दगी को इंग्लैंड की विधि के अनुसार न्यायोचित ठहराते हैं, यदि ऐसा अपराध जिसका वह अभियुक्त है, युनाइटेड किंगडम में किया गया था, तो पुलिस मजिस्ट्रेट सेक्रेट्री ऑफ स्टेट को तुरंत सुपुर्दगी का प्रमाणपत्र और मामले के संबंध में रिपोर्ट भेज कर उसके अभ्यर्पण के लिए सेक्रेट्री ऑफ स्टेट के वारंट के प्राप्त होने तक, उसे कारणागार के सुपुर्द बनाए देगा।

बंदी की सुपुर्दगी की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जो किसी भी दशा में पन्द्रह दिन से कम नहीं होगी, सेक्रेट्री ऑफ स्टेट अपने हस्ताक्षर और मोहर के अधीन आदेश द्वारा, प्रपलायी अपराधी जो ऐसे समुद्रपत्न नगर में भेजने के लिए आदेश करेगा। जिसका व्यवहार स्विस सरकार द्वारा उसकी सुपुर्दगी के लिए प्रत्येक विशेष मामले में किया जाएगा।

(ख) किसी सिद्धदोष व्यक्ति की दशा में—

कार्यवाही का अनुक्रम वही होगा, जो किसी सिद्धदोष व्यक्ति की दशा में होता है, सिवाय इसके कि उसके अध्यपेक्षा के समर्थन में स्विटजरलैंड के राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा संप्रेषित किए जाने वाले वारंट में स्पष्टरूप से ऐसा अपराध डिलिखित होगा, जिसका दावाकृत व्यक्ति सिद्धदोष ठहराया गया है और उसकी दोषसिद्धि का स्थान और तारीख का वर्णन होगा।

प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य में सिद्धदोष ठहराये गए व्यक्ति के विरुद्ध राज्य के सक्षम न्यायालय द्वारा उसके प्रत्यर्पण का दावा करने वाले राज्य के सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किया गया दण्डादेश होगा।

(ग) व्यतिक्रम में दिए गए निर्णय या ऐट डी कन्ट्रोल द्वारा सिद्धदोष ठहराये गए व्यक्तियों जो प्रत्यर्पण के मामले में अभियुक्त व्यक्ति माना जाएगा और उन्हें इस प्रकार अभ्यर्पित किया जा सकेगा।

(घ) पुलिस मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त या सिद्धदोष व्यक्ति को कारणागार में भेज दिए जाने के पश्चात् सेक्रेट्री ऑफ स्टेट द्वारा उसके अभ्यर्पण के लिए आदेश जारी किए जाने तक ऐसे व्यक्ति को बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा; यदि वह ऐसा आवेदन करता है तो उसका अभ्यर्पण रिट के विषय में न्यायालय के निर्णय तक आस्थित हो जाना चाहिए और फिर भी अभ्यर्पण केवल तभी हो सकता है जब निर्णय आवेदक के विरुद्ध हो पश्चात्वर्ती मामलों में न्यायालय उसी समय उसके अभ्यर्पण के लिए सेक्रेट्री ऑफ स्टेट के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना उसके प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को उसकी सुपुर्दगी का तत्काल आदेश दे सकेगी या ऐसे आदेश के दिए जाने तक उसे कारणागार में भेज सकेगी।

अनुच्छेद 7

ऐसी पूछताछ में जो उन्हें पूर्वगामी अनुबंधों के अनुसार करनी है, राज्य के प्राधिकारी जिन्हें यह लागू होती है, दूसरे राज्य में लिए गए अभिसाक्ष्य या साक्षियों के कथनों को, जो या तो शपथ पर लिए गए हों या निष्ठापूर्वक सत्य घोषित किए गए हों या उनकी प्रतिलिपियों को तथा इसी प्रकार उनमें जारी वारंटों और दंडादेशों या उनकी प्रतिलिपियों को समग्र रूप से विधिमान्य साक्ष्य माना जाएगा। परन्तु ऐसे दस्तावेज ऐसे राज्य के किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या प्रमाणित हों और उन पर ब्रिटेन के सेक्रेट्री ऑफ स्टेट या स्विस परिसंघ के चांसलर की सरकारी मुद्रा लगाकर अधिप्रमाणित किया गया हो।

साक्षियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बावजूद ऐसे व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए ही अपेक्षित है जिसके विरुद्ध गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के साथ कार्यवाही की जा रही है।

अनुच्छेद 8

यदि प्रत्यर्पण के समर्थन के लिए पर्याप्त सबूत गिरफ्तार व्यक्ति को पकड़े जाने की तारीख से दो मास के भीतर पेश नहीं किए जाते हैं तो उसे अभिरक्षा से मुक्त कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद 9

ऐसे मामलों में जहां आवश्यक हो स्विस सरकार का इंग्लैंड के न्यायालयों में ब्रिटेन की साम्राज्ञी के विधि अधिकारियों द्वारा और स्विस न्यायालयों में इंग्लैंड की सरकार का सक्षम स्विस प्राधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा।

संबंधित सरकारें दूसरे राज्य के प्रतिभित्रियों को, जो प्रत्यर्पण के अधीन व्यक्तियों की अभिरक्षा और सुरक्षा के लिए उनके हस्ताक्षेप का दावा करते हैं, अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के भीतर आवश्यक सहायता देगी।

इस अनुच्छेद में डिलिखित सहायता के संबंध में व्यय के प्रतिदाय के लिए किसी भी संविदाकारी पक्षकार द्वारा कोई दावा भर्ही किया जाएगा।

अनुच्छेद 10

विद्यमान संधि इस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने से पूर्व किए गए दोषों और अपराधों को लागू होंगी, किन्तु किसी अभ्यर्पित व्यक्ति पर प्रत्यर्पण से पूर्व कारित ऐसे किसी दोष या अपराध के लिए विचारण नहीं किया जाएगा, सिवाय उस अपराध के जिसके लिए उसका अभ्यर्पण मंजूर किया गया है, जो अभ्यर्पण से पहले किसी दूसरे देश में कारित किए गए थे।

अनुच्छेद 11

किसी प्रपलायी अपराधी को उस दशा में अभ्यर्पित मर्ही किया जाएगा यदि जिस अपराध के संबंध में उसके अभ्यर्पण की मांग की गई है

वह राजनीतिक स्वरूप का है या यदि वह यह साबित कर देता है कि वस्तुतः उसके अध्यर्पण की अध्यपेक्षा किसी राजनीतिक स्वरूप के अपराध के लिए उसका विचारण करने और उसे दंडित करने के उद्देश्य से की गई है।

अनुच्छेद 12

उस दशा में प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा जब अपराध किए जाने या दांडिक अभियोजन संस्थित किए जाने या उसके संबंध में सिद्धदोष ठहराए जाने के पश्चात् उसने राष्ट्र को लागू विधियों के अनुसार अभियोजन या दण से शूट प्राप्त कर ली है।

अनुच्छेद 13

उस दशा में प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा जब यूनाइटेड किंगडम की ओर से दावाकृत व्यक्ति या स्विस सरकार की ओर से दावाकृत व्यक्ति का ऐसे किसी अपराध के लिए पहले ही विचारण हो चुका है और उसे उन्मोचित या दंडित कर दिया गया हो या वह क्रमशः, स्विस अधिक्षेत्रों में से किसी एक में या यूनाइटेड किंगडम में विचारण के अधीन हो, जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण की मांग की गई है।

अनुच्छेद 14

यदि यूनाइटेड किंगडम की सरकार की ओर से दावाकृत व्यक्ति या स्विस सरकार की ओर से दावाकृत व्यक्ति क्रमशः स्विस अधिक्षेत्रों में से किसी एक में या यूनाइटेड किंगडम में किसी अन्य अपराध के लिए जांच के अधीन हो या सिद्धदोष ठहराया गया हो तो उसका प्रत्यर्पण तब तक आस्थित किया जा सकेगा जब तक कि उसे विधि के सम्यक् अनुक्रम में मुक्त नहीं कर दिया गया होगा।

यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे किसी देश में कार्यवाही की जाती है जिसमें उसने गैर-सरकारी व्यक्तियों की संविदिक वाध्यताओं के कारण शरण ली है तो प्रभावित पक्षकार द्वारा उसके सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावों को अभियोजित करने के अधिकार के रहते हुए भी उसका प्रत्यर्पण किया जाएगा।

अनुच्छेद 15

यदि विद्यमान संधि के अनुसरण में दोनों उच्च संविदाकारी पक्षकारों में से एक के द्वारा दावाकृत व्यक्ति का, एक या कई अन्य शक्तियों द्वारा उनके अपने-अपने राष्ट्रक्षेत्रों में किए गए अन्य दोनों या अपराधों के संबंध में दावा किया जाता हो तो उसका प्रत्यर्पण उस राष्ट्र को किया जाएगा जिसने प्रत्यर्पण की सबसे पहले मांग की है।

अनुच्छेद 16

अभिगृहीत ऐसी सभी वस्तुएं, जो अध्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के कब्जे में उस समय थीं जब वह पकड़ गया था, उस समय से जाएगी जब प्रत्यर्पण होता है, यदि प्रत्यर्पण के लिए उस राष्ट्र के सक्षम प्राधिकारी ने जिसे प्रत्यर्पण के लिए आवेदन किया था, उनकी सुपुर्दी का आदेश दिया हो और उक्त सुपुर्दी में केवल चुराई हुई वस्तुएं ही शामिल नहीं होंगी किन्तु ऐसी सभी वस्तुएं शामिल होंगी जिनसे अपराध साबित हो सकता हो।

जब तक ऊपर उल्लिखित वस्तुओं के संबंध में तीसरे पक्षकारों के दावे ऐसे सुपुर्दी को अनुचित नहीं ठहराते हों यह सुपुर्दी उस समय भी की जाएगी जब प्रत्यर्पण की मंजूरी दिए जाने के पश्चात् दावाकृत व्यक्ति के बच निकलने या इसकी मृत्यु के कारण प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता हो।

अनुच्छेद 17

संविदाकारी पक्षकार अध्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी और अनुरक्षण में और उसे ऐसे राज्य, जिसके लिए अध्यपेक्षा की गई है, की सीमाओं तक उसके प्रवाहण के संबंध में उनके द्वारा उपगत किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के किसी दावे को परिव्याप्त करते हैं, पारस्परिक रूप से वे ऐसे खाचों को स्वयं बहन करने के लिए सहमत हैं।

अनुच्छेद 18

विद्यमान संधि के अनुबंध ब्रिटेन की महामहिम सप्ताही के उपनिवेशों तथा उनके कब्जाधीन विदेशी क्षेत्रों पर लागू होंगे।

ऐसे किसी प्रपलायी अपराधी, जिसने ऐसे उपनिवेशों या कब्जाधीन विदेशी क्षेत्रों में से किसी में शरण ली है कि अध्यर्पिता की अध्यपेक्षा को ऐसे उपनिवेश या कब्जाधीन विदेशी क्षेत्र के राष्ट्रपाल या उच्चतम प्राधिकारी को वहां रह रहे स्विस कॉसल के माध्यम से या यदि वहां कोई स्विस कॉसल न हो तो प्रसंगत उपनिवेश या कब्जाधीन विदेशी क्षेत्र में स्विस हितों को देखने वाले दूसरे राष्ट्र के मान्यताप्राप्त कॉसलीय अधिकार्ता के माध्यम से की जाएगी।

ऊपर उल्लिखित राष्ट्रपाल या उच्चतम प्राधिकारी ऐसी अध्यपेक्षा के संबंध में विद्यमान संधि के उपर्योग के अनुसार यथासंभव निकटतम रूप से विनिश्चय करेगा। तथापि, वह प्रत्यर्पण के लिए सहमति देने या अपनी सरकार को और रिपोर्ट की सूचना देने के लिए स्वतंत्र होगा।

तथापि, ब्रिटेन की महामहिम सप्ताही विद्यमान संधि के आधार पर यथासंभव निकटतम रूप से ऐसे व्यक्तियों के, जिन्होंने इससे पूर्व उल्लिखित अपराधों में से कोई स्थितजरलैंड में किया हो और जो ब्रिटेन के उपनिवेशों और कब्जाधीन विदेशी क्षेत्रों में शरण से सकते हों, अध्यर्पण के लिए ब्रिटेन के उपनिवेशों और कब्जाधीन विदेशी क्षेत्रों में विशेष प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र होंगी।

ब्रिटेन की महामहिम सप्ताही के किसी भी उपनिवेश या कब्जाधीन विदेशी क्षेत्र से प्रपलायी अपराधी के अध्यर्पण के संबंध में अध्यपेक्षा विद्यमान संधि के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में अधिकारित नियमों द्वारा शासित होंगी।

अनुच्छेद 19

विद्यमान संधि उच्च संविदाकारी पक्षकारों की विधियों द्वारा विहित प्रस्तुतों के अनुरूप इसके प्रकाशन के दस दिन के पश्चात् प्रवृत्त हो जाएगी।

इस संधि के प्रभावी हो जाने के पश्चात् 31 मार्च, 1874 को उच्च संविदाकारी पक्षकारों के जीव हुई संधि रद्द समझी जाएगी सिवाय ऐसी किसी कार्यवाही के जो उसके आधार पर पहले ही की जा चुकी हैं या आरंभ की जा चुकी होंगी।

इस संधि को किसी भी उच्च संविदाकारी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को इसे समाप्त करने के अपने आशय की छाँ भास की सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा। किन्तु ऐसी किसी सूचना की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

इस संधि का अनुसमर्थन किया जाएगा और अनुसमर्थनों का आदान-प्रदान संभव यथा शीघ्र बन्ने में किया जाएगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप संबंधित पूर्णाधिकारी ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और उस पर अपनी मोहरें लगा दी हैं। बर्न में लार्ड के एक हजार आठ सौ अस्त्रीय वर्ष के नवम्बर मास के 26वें दिन सम्पन्न।

तारीख 29 जून, 1904 का अभिसमय निम्नलिखित उपर्युक्त करता है :—

स्विस परिसंघ की संघीय परिषद और यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के महामहिम सम्मान की सरकार ब्रिटेन के उपनिवेशों तथा कब्जाधीन विदेशी क्षेत्रों के साथ जहां तक स्विटजरलैंड का संबंध है, स्विस संघीय परिषद तथा यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन एवं आयरलैंड को महामहिम सम्मानी भारत एवं अन्य की सम्मानी के बीच 26 नवम्बर, 1880 को सम्पन्न संधि के अनुच्छेद 3 पैरा 8 और अनुच्छेद 8 द्वारा क्रमशः नियत 30 दिन और दो मास की अवधियों को अभियुक्त व्यक्तियों या सिद्धदोष व्यक्तियों के अध्यर्पण की बाबत विस्तारित करना आवश्यक समझते हुए अधोहस्ताक्षरी जो अपनी-अपनी सरकारें द्वारा इस बाबत सम्पूर्ण रूप से प्राधिकृत किए गए हैं, निम्नलिखित अनुसार सहमत हैं :—

प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 18 पहले पैरा में निम्नलिखित अनुबन्ध जोड़ा जाता है :—

जहां तक इन उपनिवेशों तथा कब्जाधीन विदेशी क्षेत्रों के साथ स्विटजरलैंड के संबंधों का संबंध है, अनुच्छेद 3 पैरा 8 द्वारा नियत समयावधि जिसके भीतर प्रत्यर्पण की अवधिपेक्षा राजनयिक माध्यम के द्वारा की जानी है, छह सप्ताह होगी, और यह कि प्रत्यर्पण अधिदिक्ष करने के लिए अनुच्छेद 8 के अधीन पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करने की अवधि तीन कलेंडर की होगी।”

विद्यमान अभिसमय अनुसर्वधनों के आदान प्रदान की तारीख से प्रभावी होगा। इसका प्रभाव और अवधि वही होगी जो 26 नवम्बर, 1880 की प्रत्यर्पण संधि की है और जिससे वह संबंधित है, इसका अनुसर्वधन किया जाएगा और अनुसर्वधनों का आदान प्रदान यथा संबंध शीघ्र लंदन में किया जाएगा।

इसके साक्षण स्वरूप अधोहस्ताक्षरी में इस विद्यमान अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं और अपनी-अपनी मोहर लगाई हैं।

29 जून, 1904 को लंदन में दो प्रतियों में सम्पन्न किया गया।

[पा. सं. टी. 413/34/96]

के. सी. सिंह, संयुक्त सचिव (सी. पी. ओ.)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Legal and Treaties Division)

ORDER

New Delhi, the 8th October, 1996

G. S. R. 462(E).—Whereas the Extradition Treaty between the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and the Swiss Federal Council was concluded and signed at Berne on the 26th November 1880, as amended by the Convention dated the 29th June 1904, are considered to be in force between India and Switzerland :

And whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), had directed by an Order number GSR 56, dated the 5th January, 1963 that the provisions of the said Act, other than Chapter III shall apply to Switzerland;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby sets out the aforesaid Treaty as under :—

“Article I

Her Majesty, the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland engages to deliver up, under the circumstances and on the conditions stipulated in the present Treaty, all persons, and the Swiss Federal Council engages to deliver up, under the like circumstances and conditions, all persons, excepting Swiss citizens, who, having been charged with, or convicted by the Tribunals of one of the two High Contracting Parties of the crimes or offences enumerated in Article II, committed in the territory of the one party, shall be found within the territory of the other.

In the event of the Federal Council being unable, by reason of his Swiss nationality, to grant the extradition of an individual, who, after having committed in the United Kingdom one of the crimes or offences enumerated in Article II, should have taken refuge in Switzerland, the Federal Council engages to give legal effect to and prosecute the charge against him according to the laws of the Canton of his origin; and the Government of the United Kingdom engages to communicate to the Federal Council all documents, depositions, and proofs relating to the case, and to cause the commissions of examination directed by the Swiss Judge, and transmitted through the proper Diplomatic channel, to be executed gratuitously.

Article II

The crimes for which the extradition is to be granted are the following :—

1. Murder (including infanticide) and attempt to murder.
2. Manslaughter.
3. Counterfeiting or altering money, uttering or bringing into circulation counterfeit or altered money.
4. Forgery, or counterfeiting, or altering, or uttering what is forged, or counterfeited, or altered; comprehending the crimes designated in the Panel Codes of both States as counterfeiting or falsification of paper money, bank notes, or other securities, forgery, or falsification of other public or private documents, likewise the uttering or bringing into circulation, or wilfully using such counterfeited, forged or falsified papers.
5. Embezzlement or larceny.
6. Obtaining money or goods by false pretences.
7. Crimes against bankruptcy law.
8. Fraud committed by a bailee, banker, agent, factor, trustee, or director, or member or public officer of any Company made criminal by any law for the time being in force.
9. Rape.
10. Abduction of minors.
11. Child stealing or kidnapping.
12. Burglary, or house breaking, with criminal intent.

13. Arson.
14. Robbery with violence.
15. Threats by letter or otherwise with intent to extort.
16. Perjury or subornation or perjury.
17. Malicious injury to property, if the offence be indictable.

The extradition is also to take place for participation in any of the aforesaid crimes, as an accessory before or after the fact, provided such participation be punishable by the laws of both Contracting Parties.

Article III

A fugitive criminal may be apprehended in either country under a warrant issued by any Police Magistrate, Justice of the Peace, or other competent authority, on such information or complaint, and such evidence, or after such proceedings as would, in the opinion of the authority issuing the warrant, justify the issue of a warrant if the crime had been committed or the person convicted in that part of the dominions of the two Contracting Parties in which the Magistrate, Justice of the Peace, or other competent authority exercises jurisdiction : provided, however, that, in the United Kingdom, the accused shall, in such case, be sent as speedily as possible before a Police Magistrate in London.

Requisitions for provisional arrest may be addressed by post or by telegraph, provided they purport to be sent by some judicial or other competent authority. Such requisitions must contain a description in general terms of the crime or offence, and a statement that a warrant has been granted for the arrest of the criminal, and that his extradition will be demanded.

He shall in accordance with this Article be discharged, as well in the United Kingdom as in Switzerland, if within the term of thirty days a requisition for extradition shall not have been made by the Diplomatic Agent of the country claiming his surrender in accordance with the stipulations of this Treaty.

Article IV

The requisition for extradition must always be made by the way of diplomacy, and to wit, in Switzerland by the British Minister to the President of the Confederation, and in the United Kingdom to the Secretary of State for Foreign Affairs by the Swiss Counsul General in London, who, for the purposes of this Treaty, is hereby recognized by Her Majesty as a Diplomatic Representative of Switzerland.

Article V

In Switzerland the manner of proceeding shall be as follows :—

The requisition for the extradition of an accused person must be accompanied by an authentic copy of the warrant of arrest, issued by a competent offical or Magistrate, clearly setting forth the crime or offence of which he is accused, together with a properly legalized information setting forth the facts and evidence upon which the warrant was granted.

If the requisition relates to a person already convicted, it must be accompanied by an authentic copy of the sentence or conviction, setting forth the crime or offence of which he has been convicted.

The requisition must also be accompanied by a description of the person claimed, and, if it be possible, by other information and particulars which may serve to identify him.

After having examined these documents, the Swiss Federal Council shall communicate them to the Cantonal Government in whose territory the person charged is found, in order that he may be examined by a judicial or police officer on the subject of their contents.

The Cantonal Government will transmit the *procès-verbal*, of the examination, together with all the documents, accompanied, if there be one, by a more detailed report to the Federal Council, who, after having examined them, and there be no opposition on either side, will grant the extradition, and will communicate its decision both to the British Legation and to the Cantonal Government in question, to the latter in order that it may send the person to be surrendered to such place on the frontier, and deliver him to such foreign police authority as the British Legation may name in each special case.

Should the documents furnished with a view of proving the facts, or of establishing the identity of the accused, or the particulars collected by the Swiss authorities appear insufficient, notice shall be immediately given to the Diplomatic Representative of Great Britain, in order that he may furnish further evidence if such further evidence be not furnished within fifteen days the person arrested shall be set at liberty.

In the event of the application of this Treaty being contested, the Swiss Federal Council will transmit the documents ("dossier") to the Swiss Federal Tribunal, whose duty it is to decide definitely the question whether extradition should be granted or refused.

The Federal Council will communicate the judgment of the Federal Tribunal to the British Legation. If this judgment grants the extradition the Federal Council will order its execution, as in the case when the Federal Council itself grants the extradition. If, on the other hand, the Federal Tribunal refuses the extradition, the Federal Council will immediately order the person accused to be set at liberty.

Article VI

In the dominions of Her Britannic Majesty, other than the Colonies or foreign possessions of Her Majesty, the manner of proceeding shall be as follows :—

- a. In the case of a person accused :

The requisition for the surrender shall be made to Her Britannic Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs by the Diplomatic Representative of the Swiss Confederation. The said demand shall be accompanied by a warrant of arrest, or other equivalent judicial document, issued by a Judge or Magistrate duly authorised to take cognizance of the acts charged against the accused in Switzerland, and duly authenticated depositions or

statements taken on oath, or solemnly declared to be true, before such Judge or Magistrate, clearly setting forth the said acts, and containing a description of the person claimed, and any particulars which may serve to identify him.

The said Principal Secretary of State shall transmit such documents to Her Britannic Majesty's Principal Secretary of State for the Home Department, who shall then, by order under his hand and seal, signify to some Police Magistrate in London that such requisition has been made, and require him, if there be due cause, to issue his warrant for the apprehension of the fugitive. On the receipt of such order from the Secretary of State, and on the production of such evidence as would, in the opinion of the Magistrate, justify the issue of the warrant if the crime had been committed in the United Kingdom, he shall issue his warrant accordingly.

When the person claimed shall have been apprehended, he shall be brought before the Magistrate who issued the warrant, or some other Police Magistrate in London. If the evidence to be then produced shall be such as to justify, according to the law of England, the committal for trial of the prisoner, if the crime of which he is accused had been committed in the United Kingdom, the Police Magistrate shall commit him to prison to await the warrant of the Secretary of State for his surrender, sending immediately to the Secretary of State a certificate of the committal and a report upon the case.

After the expiration of a period from the committal of the prisoner, which shall never be less than fifteen days, the Secretary of State shall, by order under his hand and seal, order the fugitive criminal to be sent to such seaport-town as shall, in each special case, be selected for his delivery to the Swiss Government.

b. In the case of a person convicted :—

The course of proceeding shall be the same as in the case of a person accused, except that the warrant to be transmitted by the Diplomatic Representative of Switzerland in support of his requisition shall clearly set forth the crime or offence of which the person claimed has been convicted, and state the place and date of his conviction.

The evidence to be produced shall consist of the penal sentence passed against the convicted person by the competent Court of the State claiming his extradition.

c. Persons convicted by judgment in default or *arrêt de contumace* shall be, in the matter of extradition, considered as persons accused, and may, as such, be surrendered.

d. After the Police Magistrate shall have committed the accused or convicted person to prison to await the order of a Secretary of State for his surrender, such person, shall have the right to apply for a writ of *habeas corpus*; if he should so apply, his surrender must be deferred until after the decision of the Court upon the return to the writ, and even then can only take place if the decision is adverse to the applicant. In the latter case, the Court may at once order his delivery to the

person authorized to receive him, without waiting for the order of a Secretary of State for his surrender, or commit him to prison to await such order.

Article VII

In the examinations which they have to make in accordance with the foregoing stipulations, the authorities of the State applied to shall admit as entirely valid evidence the depositions or statements of witnesses, either sworn or solemnly declared to be true, taken in the other State, or copies thereof, and likewise the warrants and sentences issued therein, or copies thereof, provided such documents purport to be signed or certified by a Judge, Magistrate, or officer of such State, and are authenticated by the official seal of a British Secretary of State, or of the Chancellor of the Swiss Confederation being affixed thereto.

The personal attendance of witnesses can be required only to establish the identity of the person who is being proceeded against with that of the person arrested.

Article VIII

If proof sufficient to warrant the extradition be not furnished within two months from the day of the apprehension, the person arrested shall be discharged from custody.

Article IX

In cases where it may be necessary, the Swiss Government shall be represented at the English Courts by the Law Officer of the Crown, and the English Government in the Swiss Courts by the competent Swiss authorities.

The respective Governments will give the necessary assistance within their territories to the Representatives of the other State who claim their intervention for the custody and security of the persons subject to extradition.

No claim for the repayment of expenses for the assistance mentioned in this Article shall be made by either of the Contracting Parties.

Article X

The present Treaty shall apply to crimes and offences committed prior to the signature of the Treaty; but a person surrendered shall not be tried for any crime or offence committed in the other country before the extradition other than the crime for which his surrender has been granted.

Article XI

A fugitive criminal shall not be surrendered if the offence in respect of which his surrender is demanded is one of a political character, or if he proved that the requisition for his surrender has, in fact, been made with a view to try and punish him for an offence of a political character.

Article XII

The extradition shall not take place if, subsequently to the commission of the crime, or the institution of the penal prosecution, or the conviction thereon, exemption from prosecution or punishment has been acquired according to the

laws of the State applied to.

Article XIII

The extradition shall not take place if the person claimed on the part of the Government of the United Kingdom, or the person claimed on the part of the Swiss Government, has already been tried and discharged or punished, or is still under trial, in one of the Swiss Cantons or in the United Kingdom respectively, for the crime for which his extradition is demanded.

Article XIV

If the person claimed on the part of the Government of the United Kingdom, or if the person claimed on the part of the Swiss Government, should be under examination, or have been condemned for any other crime, in one of the Swiss Cantons or in the United Kingdom respectively, his extradition may be deferred until he shall have been set at liberty in due course of law.

In case such individual should be proceeded against in the country in which he has taken refuge, on account of obligations contracted towards private individuals, his extradition shall, nevertheless, take place, the injured party retaining his right to prosecute his claims before the competent authority.

Article XV

If the individual claimed by one of the two High Contracting Parties in pursuance of the present Treaty should be also claimed by one or several other Powers, on account of other crimes or offences committed upon their respective territories, his extradition shall be granted to that State whose demand is earliest in date.

Article XVI

All articles, seized, which were in the possession of the person to be surrendered at the time of his apprehension, shall, if the competent authority of the State applied for the extradition has ordered the delivery thereof, be given up when the extradition takes place, and the said delivery shall extend not merely to the stolen articles, but to every thing that may serve as a proof of the crime.

This delivery shall take place even when the extradition, after having been granted, cannot be carried out by reason of the escape or death of the individual claimed, unless the claims of third parties with regard to the above-mentioned articles render such delivery inexpedient.

Article XVII

The Contracting Parties renounce any claim for the reimbursement of the expences incurred by them in the arrest and maintenance of the person to be surrendered, and his conveyance to the frontiers of the State to which the requisition is made; they reciprocally agree to bear such expenses themselves.

Article XVIII

The stipulations of the present Treaty shall be applicable to the Colonies and foreign possessions of her Britannic

Majesty.

The requisition for the surrender of a fugitive criminal who has taken refuge in any of such Colonies or foreign possessions shall be made to the Governor or to the supreme authority of such Colony or possession through the Swiss Consul residing there, or in case there should be no Swiss Consul, through the recognized Consular Agent of another State charged with the Swiss interests in the Colony or possession in question.

The Governor or supreme authority above-mentioned shall decide with regard to such requisitions as nearly as possible in accordance with the provisions of the present Treaty. He will, however, be at liberty either to consent to the extradition or report the case to his Government.

Her Britannic Majesty shall, however, be at liberty to make special arrangements in the British Colonies and foreign possessions for the surrender of such individuals as shall have committed in Switzerland any of the crimes hereinbefore mentioned, who may take refuge within such Colonies and foreign possessions, on the basis, as nearly as may be, of the provisions of the present Treaty.

The requisition for the surrender of a fugitive criminal from any Colony or foreign possession of Her Britannic Majesty shall be governed by the rules laid down in the preceding Articles of the present Treaty.

Article XIX

The present Treaty shall come into force ten days after its publication in conformity with the forms prescribed by the laws of the High Contracting Parties.

After the Treaty shall have come into force, the Treaty concluded between the High Contracting Parties on the 31st of March, 1874, shall be considered as cancelled, except as to any proceedings that may have been already taken or commenced in virtue thereof.

It may be terminated by either of the High Contracting Parties, on giving to the other party six months' notice of its intention to terminate the same, but no such notice shall exceed the period of one year.

The Treaty shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at Berne as soon as possible.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the same, and have affixed thereto the seal of their arms.

Done at Berne, the twenty-sixth day of November, in the year of our Lord one thousand eight hundred and eighty".

The Convention dated 29 June, 1904 provides as follows:

The Federal Council of the Swiss Confederation and the Government of His Majesty the King of the United King-

dom of Great Britain and Ireland, having deemed, it necessary to extend, so far as regards the relations of Switzerland with the British Colonies and foreign possessions, the periods of thirty days and two months respectively fixed by Article III, paragraph 8, and Article VIII, of the Treaty concluded on the 26th November, 1880, between the Swiss Federal Council and Her late Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Empress of India, &c., respecting the extradition of persons accused or condemned, the Undersigned, duly authorized to that effect by their respective Governments, have agreed as follows:—

The following stipulation is added to the first paragraph of Article XVIII of the Treaty of Extradition:

“Nevertheless, so far as regards the relations of Switzerland with these Colonies and foreign possessions, the

period of time fixed by Article III, paragraph 8, within which the requisition for extradition is to be made through the diplomatic channel, shall be six weeks; and that provided by Article VIII for the production of proof sufficient to warrant the extradition shall be three calendar months.”

The present Convention shall come into force from the date when the ratifications shall be exchanged. It shall have the same force and duration, as the Treaty of Extradition of the 26th November, 1880, to which it relates.

It shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at London as soon as possible.

In witness whereof the undersigned have signed the present Convention, and have affixed their seals thereto.

Done at London, in duplicate, the 29th day of June, 1904.”

[File No. T. 413/34/96]

K.C. SINGH, Jt. Secy. (CPV)

